

# प्रवाह

महोत्सव विश्वास का



निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक  
स्थापना वर्ष : 1948

प्रेम के माध्यम से त्याग और विवेक की भावना स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाती है।  
- रामकृष्ण परमहंस

मास्को ने यूक्रेन पर अपने राष्ट्रपति भवन को निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए बदला लेने की जो धमकी दी है, उससे साफ है कि वह यूक्रेन पर हमले तेज करने वाला है। कम से कम अब तो संयुक्त राष्ट्र जैसी विश्व संस्था को यह युद्ध रोकने के लिए सक्रिय होना चाहिए।

## पुतिन की मंशा

यूक्रेन पर युद्ध थोपने के करीब चौदह महीने बाद रूस ने उस पर ड्रोन हमले कर पुतिन की जान लेने की साजिश रचने का जो आरोप लगाया है, उससे उसके ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम पर ही सबसे पहले सवाल खड़े होते हैं। वैसे तो यूक्रेन जैसे छोटे-से देश के खिलाफ इतने लंबे समय से जारी युद्ध ही बता देता है कि रूस की सैन्य शक्ति उतनी भी मजबूत नहीं है। लेकिन जो देश महाशक्ति अमेरिका से होड़ करता हो, उसके राष्ट्रपति की अचूक सुरक्षा व्यवस्था के बारे में कहीं कोई शक नहीं है। ऐसे में, यह भला कैसे संभव है कि दो ड्रोन मास्को के आकाश में अबाध उड़ान भरते हुए सीधे राष्ट्रपति भवन तक पहुंच जाएं और किसी को खबर न हो? तथ्य यह भी है कि यूक्रेन पर आरोप लगाने के बावजूद रूस कोई सबूत पेश नहीं कर पाया है। इसके बजाय उसका कहना था कि विजय दिवस (नौ मई) से पहले राष्ट्रपति पुतिन की हत्या की

कोशिश आतंकी कृत्य है, जिसका बदला लिया जाएगा। बल्कि अब तो उसने नया आरोप लगाया है कि क्रैमलिन को निशाना बनाने की साजिश यूक्रेन में नहीं, अमेरिका में रची गई थी। यूक्रेन ने हालांकि रूस के इस आरोप का खंडन किया है, पर युद्ध के मोर्चे पर वह मजबूत सैन्य कार्रवाई की तैयारी में है। जब रूस का आरोप सामने आया, तब राष्ट्रपति जेलेन्स्की उन नॉर्डिक देशों के दौरे पर थे, जो यूक्रेन के सबसे बड़े समर्थक हैं और जिन्होंने उसे और मदद देने का वादा किया। वहां से जेलेन्स्की हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय गए, जहां उन्होंने कहा कि युद्ध में यूक्रेन की विजय के बाद पुतिन को युद्धपराध के मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। इस पृष्ठभूमि में रूस के आरोप और समय पर इसका समुचित जवाब देने की उसकी धमकी बताती है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन पर रूसी हमले तेज होने वाले हैं। रूसी रक्षा प्रमुख द्वारा मिसाइल उत्पादन दौंगना करने की बात से भी मास्को के आक्रामक इरादे साफ हैं। दूसरी ओर,



अमेरिका, यूरोपीय संघ और दूसरे देशों की सैन्य व आर्थिक मदद के कारण यूक्रेन न सिर्फ इतने दिनों से रूस के खिलाफ मोर्चे पर टिका हुआ है, बल्कि उसे नुकसान पहुंचाने में भी समर्थ है। संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्था की भूमिका इस मामले में अभी तक तो अप्रभावी ही रही है। लेकिन कम से कम अब रूस के तेवर को संयुक्त राष्ट्र समेत दूसरे बड़े देशों को गंभीरता से लेना ही चाहिए।



डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (1888-1975)

## आजादी के अमृत कथन

गुटंबंदी से अलगाव और सह-जीवन हमारी विदेश नीति के दो बुनियादी सिद्धांत हैं। हमारा हमेशा यह दृढ़ विश्वास रहा है कि इंसान की तरक्की के लिए शांति बहुत जरूरी है।

## इंसान की तरक्की के लिए शांति बहुत जरूरी है

सदस्यगण, संसद के नए अधिवेशन का कार्यभार उठाने के लिए मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। हाल ही में जो साल समाप्त हुआ है, उसमें हमारा देश परीक्षा की एक ऐसी घड़ी से गुजरा, जो पिछले कुछ वर्षों में सबसे कठिन कहा जा सकता है। जनता ने अपने प्यारे नेता जवाहरलाल नेहरू को खो दिया; जो लोगों के मित्र, शुभचिंतक और पथ-प्रदर्शक थे। इसके अलावा और भी बहुत-सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दक्षिण भारत में अभूतपूर्व तूफानों से जो भारी हानि हुई, उससे हमें बड़ा दुख पहुंचा। हमारे सामने अब भी कुछ ऐसी कठिनाइयाँ हैं, जिनका मुकाबला हमें हिम्मत और मुस्तेदी के साथ करना है। इनके बावजूद देश ने अनेक दिशाओं में



महत्वपूर्ण प्रगति की है। पिछले 12 महीनों में हमें विशेष सफलताएं प्राप्त हुई हैं, जो हममें आशा व विश्वास का संचार करती हैं। तीसरी योजना के पहले दो वर्षों में देश की आमदनी मात्र 2.5 फीसदी प्रतिवर्ष की दर से बढ़ी थी। 1963-64 में औद्योगिक उत्पादन में 9.2 फीसदी की वृद्धि होने से आमदनी बढ़कर 4.3 फीसदी हो गई है। चालू वर्ष के दौरान औद्योगिक उत्पादन में करीब आठ फीसदी तक की वृद्धि होने की आशा है। बिजली और परिवहन के क्षेत्र में हमारा देश निरंतर प्रगति कर रहा है। पहली योजना के शुरू में जिन गांवों को बिजली दी गई थी, उनकी संख्या 4,000 थी। अब वह बढ़कर करीब 40,000 हो गई है। एक महत्वपूर्ण बात यह हुई कि आम आदमी के काम आने वाली कई चीजें और अधिक मात्रा में मिलने लगी हैं। औद्योगिक क्षेत्र में हमारा पिछला रिकॉर्ड अच्छा रहा है, फिर भी उसमें नए सिरे से गतिशीलता लाने की आवश्यकता है। यह न केवल मूल्यों को स्थिर करने के लिए ही आवश्यक है, बल्कि अधिक उत्पादन के लिए भी।

देश की जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण खेती और उद्योग, दोनों ही क्षेत्रों में उत्पादन की रफ्तार तेज करना बहुत जरूरी हो गया है। 1951 व 1961 के बीच देश की आबादी 36 करोड़ से 44 करोड़ हो गई और अगर इसी रफ्तार से यह बढ़ती रही, तो तीसरी योजना के अंत में 49 करोड़, और चौथी योजना के अंत में 55 करोड़ हो जाएगी। राष्ट्र के लिए यह बहुत आवश्यक है कि परिवार सीमित रखे जाएं। परिवार परिसीमन नियोजन की समिलित सेवा तैयार की गई है, जिसमें परिवार परिसीमन और जन्म-बन्धा के कल्याण का ध्यान रखा जाएगा। करीब 12,000 परिवार नियोजन केंद्र खोले जा चुके हैं। ठीक योजनार्थ बनाया तो जरूरी है ही, पर जहां तक जन-सामान्य का प्रश्न है, संतोषजनक ढंग से परिणाम तभी प्राप्त किए जा सकते हैं, जब योजनाओं और नीतियों पर अमल करने वाला प्रशासन-तंत्र तेजी, होशियारी और ईमानदारी से काम करे। इसलिए सरकार यह प्रयत्न करे कि प्रशासन-तंत्र में सुधार किया जाए।

सभी देशों के साथ हमारे संबंध दोस्ती के हैं। सिर्फ चीन ने हमारी तरफ दुश्मनी का रुख अख्तियार कर लिया है। बर्दकिसती से पाकिस्तान के साथ भी हमारे संबंधों में कोई सुधार नहीं हुआ। गुटबंदी से अलगाव और सह-जीवन हमारी विदेश नीति के दो बुनियादी सिद्धांत हैं। हमारा हमेशा यह दृढ़ विश्वास रहा है कि इंसान की तरक्की के लिए शांति बहुत जरूरी है। दुनिया के जो देश विकास की ओर बढ़ रहे हैं, उनके लिए तो यह और भी जरूरी है, क्योंकि उनको बड़ी-बड़ी समस्याओं का सामना करना है।

-राष्ट्रपति द्वारा 17 फरवरी, 1965 को संसद के संयुक्त अधिवेशन में दिए गए भाषण के संघारित अंश।

## संतुलन बिठाने की कोशिश में बांग्लादेश

बांग्लादेश एक तरफ भारत और चीन के बीच संतुलन बिठाने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ हिंद-प्रशांत क्षेत्र को भी महत्व दे रहा है।

लेकिन देखने वाली बात यह है कि वह किसी भी सुरक्षा गठबंधन से दूर रहने का संकेत दे रहा है।

महाशक्ति देशों में हिंद-प्रशांत क्षेत्र को लेकर बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच बांग्लादेश ने अपना हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण पेश किया है। यह नीति दस्तावेज शेख हसीना के अमेरिका, ब्रिटेन और जापान दौरे के ठीक पहले जारी किया गया है। ये देश हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रमुख खिलाड़ी हैं। इसके अलावा, अमेरिका और जापान कवाड के भी महत्वपूर्ण सदस्य हैं।

शेख हसीना जिन देशों की यात्रा करने वाली हैं, वे बांग्लादेश के महत्वपूर्ण आर्थिक और व्यापारिक साझेदार हैं। वे बांग्लादेशी उत्पादों, विशेष रूप से रॉडमेड वस्त्रों के महत्वपूर्ण गंतव्य हैं। बांग्लादेश उन्हें प्रमुख विकास भागीदारों के रूप में भी शामिल करने की उम्मीद रखता है, जो खुद निम्न आय वर्ग वाले देशों से मध्यम आय वाले देशों की श्रेणी में आ गया है। लेकिन इसने आर्थिक क्षेत्र में उसके लिए विशेष चुनौतियां भी पेश की हैं।

बांग्लादेश जीएसपी जैसी कुछ सुविधाओं को खो देगा, जिससे उसके उत्पादों को इन बाजारों में प्रवेश करने में मदद की। ऐसे में उसे बड़ी हुई प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बांग्लादेश को हिंद-प्रशांत के प्रति अपने दृष्टिकोण में स्पष्टता लाने की आवश्यकता थी, ताकि वह अपने निर्यात बाजारों में विशेषाधिकार प्राप्त करता रहे। यह सर्वविदित है कि चीन ने हिंद-प्रशांत देशों में गहरी पैठ बना ली है, जिसमें दक्षिण एशिया भी शामिल है। वहां बढ़ते तनाव ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को अपनी हिंद-प्रशांत रणनीति के साथ सामने आने के लिए मजबूर कर दिया है। ज्यादातर मामलों में चीन पर अंकुश इन रणनीतियों का केंद्रीय विषय है। चूंकि चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और सैन्य हार्डवेयर आपूर्तिकर्ता है, इसलिए बांग्लादेश के लिए हिंद-प्रशांत को लेकर एक स्टैंड लेना आसान नहीं रहा है। बांग्लादेश चीन की समुद्री सिक्रेट रोड परियोजना का भी सक्रिय भागीदार है, जो चीनी बीआरआई का हिस्सा है। इसके अलावा,



चीन बांग्लादेश में कई ढांचगत परियोजनाओं में लगा हुआ है। दरअसल इन कोशिशों के जरिये चीन हिंद महासागर में घुसने और इसके सुरक्षा माहौल को बदलने की कोशिश करता रहा है।

चीन जानता है कि अमेरिका और उसके सहयोगियों की हिंद-प्रशांत रणनीति में सुरक्षा का मुद्दा शामिल है। बांग्लादेश में चीनी राजदूत याओ वेन ने ढाका में आयोजित एक संवाद में इसका संकेत दिया था। उन्होंने बांग्लादेश को कवाड में शामिल होने के प्रति चेतावनी दी थी, जिस पर बांग्लादेश ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और इसे अपने आंतरिक मामलों में दखल नाथ। उसने चीन को यह भी संकेत दिया कि वह विदेश नीति में स्वायत्तता बनाए रखना चाहता है।

हिंद-प्रशांत को लेकर अपना नजरिया स्पष्ट करने के लिए ही बांग्लादेश ने 'इंडो-पैसिफिक आउटलुक' जारी किया है। इसमें रणनीति (स्ट्रेटजी) के बदले दृष्टिकोण (आउटलुक) शब्द का प्रयोग जान-बूझकर किया गया है, क्योंकि इसका अर्थ नरम है। यह दस्तावेज जारी करते हुए बांग्लादेश के विदेश मंत्री शहरयार आलम ने कहा कि 'वैश्विक जीडीपी में हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सामूहिक हिस्सेदारी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रमुखता, बढ़ती जलवायु कार्रवाई और बढ़ती तकनीकी गतिशीलता बांग्लादेश के दीर्घकालिक लचीलेपन और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख निर्धारक हो सकते हैं।' दस्तावेज में बांग्लादेश 'सबकी साझा समृद्धि के लिए एक स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, सुरक्षित और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र की कल्पना करता है।' इस दस्तावेज के चार मार्गदर्शक सिद्धांत और पंद्रह उद्देश्य हैं। मार्गदर्शक सिद्धांतों का मुख्य ध्यान शेख मुजीबुर रहमान की विदेश नीति के सिद्धांत 'सभी के प्रति मित्रता, किसी

के प्रति द्वेष नहीं' पर है। यह संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में बल प्रयोग के त्याग की भी बात करता है। यह संयुक्त राष्ट्र संधियों, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूनसोएलओएस) के पालन पर जोर देता है और सतत विकास के लिए रचनात्मक क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सहयोग चाहता है। दस्तावेज के उद्देश्य खंड में वह चाहता है कि सभी देश हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और सुरक्षा पर मौजूदा तंत्र को मजबूत करें और अंतरराष्ट्रीय कानून और यूनसोएलओएस के अनुसार नौवहन की स्वतंत्रता और उड़ान भरने की कवायद को बनाए रखें।

बांग्लादेश भी खुले, पाददर्शी, नियम आधारित बहुपक्षीय प्रणालियों को बढ़ावा देना चाहता है, जो हिंद-प्रशांत और उससे परे समान और सतत विकास को सक्षम बनाता हो। इसमें हिंद-प्रशांत में निर्बाध वाणिज्य प्रवाह के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है। साफ है कि बांग्लादेश व्यापार व वाणिज्य में दिलचस्पी रखता है। शेख हसीना द्वारा कुछ महत्वपूर्ण देशों की यात्रा से पहले इस दस्तावेज को जारी करने की मुख्य वजह यह है कि बांग्लादेश उन देशों से अधिकतम आर्थिक लाभ उठाना चाहता है। साथ ही, इसे केवल आर्थिक पहलू तक सीमित करके यह संकेत दिया गया है कि वह किसी भी सुरक्षा गठबंधन का हिस्सा नहीं होगा। ऐसा करके उसने चीन को शांत करने की कोशिश की है, जिसे डर था कि बांग्लादेश चीन विरोधी गठबंधन में शामिल हो सकता है।

कुछ लोगों का कहना है कि भारत के साथ घनिष्ठता के कारण बांग्लादेश इस दिशा में आगे बढ़ा है, लेकिन यह सच नहीं हो सकता। भारत के लिए चीन शत्रुतापूर्ण पड़ोसी है, जिस पर नियंत्रण जरूरी है। लेकिन बांग्लादेश दोनों के साथ संतुलन बिठाने की कोशिश कर रहा है। इस दृष्टिकोण को उसके 'इंडो-पैसिफिक आउटलुक' में भी देखा जा सकता है, जहां बांग्लादेश ने किसी भी सुरक्षा गठबंधन से दूर रहने की कोशिश की है।

बांग्लादेश में आगामी जनवरी में चुनाव होने वाले हैं। अगर उस चुनाव को पश्चिमी देशों द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं माना गया, तो वे बांग्लादेश से अपने निरंतेरक कम कर सकते हैं। वैसे में अंतरराष्ट्रीय पटल पर भारत और चीन उसके मुख्य समर्थक साबित हो सकते हैं। इस पृष्ठभूमि में बांग्लादेश द्वारा जारी दस्तावेज को उसकी संपूर्णता में समझा जा सकता है। उसने हिंद-प्रशांत क्षेत्र को महत्व दिया है, क्योंकि आर्थिक महाशक्तियां इसी क्षेत्र में हैं, लेकिन वह किसी के पक्ष में खुलेआम नहीं दिखना चाहता।

-एसोसिएट फेलो, एमपी-आईडीएएस।

यदि वृक्ष के नीचे पड़े फल को प्राप्त करने की लालसा हो, तो वृक्ष के प्रति आभार व्यक्त करने के बाद ही उसे ग्रहण करना चाहिए।

## अनूठी सीख



अंतर्गमना शिवकुमार गोदल

भगवान बुद्ध एक दिन किसी गांव की ओर जा रहे थे। रास्ते में विश्राम के लिए वह एक तालाब के किनारे वृक्ष के नीचे बैठ गए। तालाब में कमल के पुष्प खिले थे। कमल पुष्पों की अनूठी छटा देखकर वह अभिभूत हो उठे तथा जल में उतर पड़े। कमल की अनूठी सुगंध से वह सुध-बुध खो बैठे। जैसे ही वह बाहर निकले कि देवकन्या की वाणी उन्हें सुनाई दी, 'महात्मन, आपने बिना कुछ दिए इन पुष्पों की सुगंध का सेवन किया। यह चौर-कर्म है।' तथागत ने ये शब्द सुने, तो हतभंग खड़े रहे। अचानक एक व्यक्ति तालाब में उतरकर कमल तोड़ने लगा। देवकन्या उसे कमल तोड़ते देखती रही। तथागत ने कहा, 'देवी, मैंने तो केवल सुगंध

लिया था, स्पर्श भी नहीं किया, तुमने मुझे चौर कह दिया। यह फूलों को तोड़ रहा है। तुम इसे क्यों नहीं रोक रही?' देवकन्या ने कहा, 'भगवान, सांसारिक मानव अपने लाभ के लिए धर्म-अधर्म में भेद नहीं कर पाता। ऐसा अज्ञानी व्यक्ति क्षम्य है, किंतु जिसका अवतार धर्म प्रचार के लिए हुआ है, उसे तो प्रत्येक कृत्य के उचित-अनुचित का विचार करना चाहिए।' तथागत समझ गए कि यह देवकन्या साधारण नहीं है। उन्होंने शिष्यों से कहा, 'यदि वृक्ष के नीचे पड़े फल को प्राप्त करने की लालसा हो, तो वृक्ष के प्रति आभार व्यक्त करने के बाद ही उसे ग्रहण करना चाहिए।'

(अमर उजाला आकहेव से)

## साझा संस्कृति के प्रतीक हैं बुद्ध

संस्कृत कवि क्षेमेंद्र द्वारा लिखे दशावतार-चरित में एवं जयदेव द्वारा लिखे गीतगोविंद में बुद्ध को विष्णु का अवतार माना गया है।

शास्त्री कोसलेन्द्रदास

बुद्ध जयंती



पंचशील के पालन की प्रेरणा दी है। उनके मत से पंचशील के पालन से व्यक्ति की आत्मिक उन्नति होती है और वह ज्ञान पाने के योग्य होता है। ये पंचशील हैं-हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना एवं नशा न करना। प्रायः लोग धर्मराज के नाम से महाभारत के

## भूली बिसरी दस्तावेज

## लियाकत और जिन्ना गुरु गुड़ तो चेला शककर

दो नेता और मोहब्बत। हालात एक से। लेकिन एक के लिए मोहब्बत मंजिल पर पहुंचने की ताकत बनी, तो दूसरे ने उसे सियासत की राह में पैरों की जंजीर समझा। वे नेता थे-मोहम्मद अली जिन्ना और पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान।

ऐतिहासिक किंवदंतियों के लोकप्रिय लेखक राजगोपाल सिंह वर्मा ने इस किस्से को अपनी नई किताब 'पहली औरत...राना लियाकत बेगम' में बखूबी विश्लेषित किया है। करनाल के नवाबजादा और मुजफ्फरनगर के जागीरदार लियाकत अली खान ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से पढ़कर आए थे। मोहम्मद अली जिन्ना उनके राजनीतिक गुरु और आदर्श थे। दोनों की दूसरी पत्नियों आधुनिक विचारधारा की थीं, उम्र में उनसे छोटी थीं, दूसरे धर्म की थीं और विवाह के लिए इस्लाम धर्म अपनाने को राजी हो गई थीं। पर यह समानता बस यहीं तक थी। जिन्ना का वैवाहिक जीवन कुछ ही वर्षों में विखरने लगा था। जिन्ना को अपने मित्र सर दिनशा पेंटेट की बेटी रूटी से इश्क हुआ था, जो सोलह वर्ष की थी, जबकि जिन्ना चालीस के थे। रूटी ने अट्ठारह वर्ष की होते ही जिन्ना से निकाह कर लिया। पर वक्त गुजरने के साथ वह समझने लगी कि यह बेमेल उम्र का प्यार था। दोनों का मिजाज अलग था। जिन्ना राजनीति में दृढ़ते गए और अंततः दोनों अलग हो गए। अवसाद और अन्य बीमारियों के चलते रूटी को बचाया नहीं जा सका।

दूसरी ओर, लियाकत अली खान को राना बेगम से अगाध प्रेम था। अल्मोड़ा की आइरीन पंत यानी राना बेगम हर मामले में पति की सच्ची अर्धांगिनी थी। यह वह समय था, जब देश की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई जा रही थी। लियाकत अली खान और राना बेगम की शादी से दो साल पहले ही दिल्ली को राजधानी का दर्जा मिला था। उन्होंने 8-बी हाईवे एवेन्यू को अपना नया घर बनाया, जिसे आज हम तिलक मार्ग के नाम से जानते हैं। तब तक जिन्ना स्वतंत्रता आंदोलन का चर्चित नाम बन चुके थे और अक्सर इस युगल के मेहमान हुआ करते थे। कांग्रेसी जिन्ना बाद में मुस्लिम लीग के सदस्य बने। फिर भी वह कांग्रेस के साथ बने रहे, जहां वह हिंदू-मुस्लिम एकता की वकालत करते। पर कांग्रेस में महात्मा गांधी का प्रभाव बढ़ते ही जिन्ना ने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया। सन 1928 में साइमन कमीशन के भारत आने पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने इसका विरोध करना तय कर लिया था। तब लियाकत अली खान अपने नेता के साथ खड़े थे। आइरीन ने भी तब अपने सक्रिय सहपाठियों के साथ साइमन कमीशन का विरोध किया था।

मोहम्मद अली जिन्ना लियाकत अली खान के गुरु थे। दोनों की दूसरी पत्नियां आधुनिक विचारधारा की, दूसरे धर्म की और उम्र में उनसे छोटी थीं।

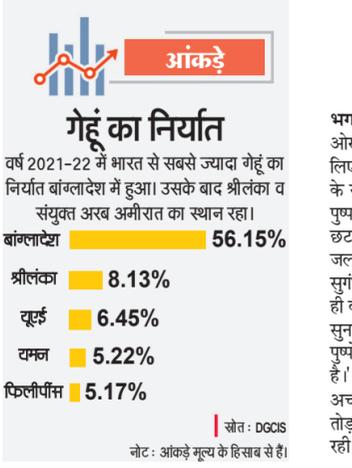


विनोद पुरोहित

लेकिन जिन्ना के लिए मोहब्बत जहां राजनीति के रास्ते की बाधा बनी, वहीं लियाकत अली के लिए मोहब्बत मंजिल पर पहुंचने की ताकत साबित हुई।



साइमन कमीशन का विरोध लियाकत अली के साथ उनकी पत्नी राना बेगम ने भी किया था, जबकि जिन्ना की दूसरी पत्नी उनसे अलग हुई और चल बसी।



बीती ढाई सहस्राब्दियों से जिस दर्शन की गूंज व्यापक रूप से छाई है, वह बौद्ध दर्शन है। शुरू में यह दार्शनिक प्रस्थान मात्र था, जो धीरे-धीरे धर्म के रूप में परिवर्तित हो गया और अनेक लोग इससे जुड़ते गए। बौद्ध दर्शन चिंतन-मूलक है। जो बुद्ध के चिंतन में आया, वही बौद्ध दर्शन का आधार है। बौद्ध दर्शन के उपदेश में बुद्ध की करुणा ही एकमात्र कारण है। उनके अनुसार सत्य के दो प्रकार हैं- पारमार्थिक एवं सांवृतिक। पारमार्थिक सत्य ही शून्य है और सांवृतिक है संसार का सत्य। जितने भी सांवृतिक सत्य हैं, वे क्षणभंगुर हैं। पारमार्थिक सत्य के साक्षात्कार ही जन्म-मरण के चक्र से छुटकारा मिल सकता है। बुद्ध के उपदेशों के अनुसार, पंचशील के अनुष्ठान एवं दार्शनिक ज्ञान के अभ्यास से निर्वाण प्राप्त होता है। गौतम बुद्ध ने अपने अनुयायियों को कठोरता से

## अमर उजाला

पुराने पन्नों से 11 दिसंबर, 1971

## जिन्नेवा समझौते का पूरी तरह अमल करता है भारत

### जिन्ना समझौते पर पूर्ण अमल

नई दिल्ली, 11 दिसंबर : भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक वक्तव्य में गुट-दोहारा है कि भारत वायव्य और बीमार सैनिकों, युद्ध बंदियों के साथ व्यवहार और नागरिकों की सुरक्षा के बारे में पूरी तरह से जिन्ना समझौते का पालन कर रहा है।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की अपील पर इस तथ्य को पुनः दोहराया है कि भारत घायल व बीमार सैनिकों, युद्ध बंदियों के साथ व्यवहार और नागरिकों की सुरक्षा के बारे में पूरी तरह से जिन्ना समझौते का पालन कर रहा है।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की अपील पर इस तथ्य को पुनः दोहराया है कि भारत घायल व बीमार सैनिकों, युद्ध बंदियों के साथ व्यवहार और नागरिकों की सुरक्षा के बारे में पूरी तरह से जिन्ना समझौते का पालन कर रहा है।

edit@amarujala.com